भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 764
गुरुवार, 24 जुलाई, 2025/2 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

पीड़ितों को मुआवज़ा

764. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ऐसी कोई विशिष्ट नीति या नियम नहीं है जो एयरलाइनों को विमान दुर्घटना के कारण जमीन पर अपनी जान या संपत्ति गँवाने वाले निर्दोष नागरिकों को समय पर और पर्याप्त मुआवजा देने के लिए बाध्य करता हो, जबकि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन ऐसी दुर्घटनाओं में मरने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य और समयबद्ध मुआवज़ा सुनिश्चित करता है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार यह उचित मानती है कि जमीन पर हुए पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा पाने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़े, जबकि नुकसान सीधे एयरलाइन के संचालन के कारण हुआ हो और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की कोई स्पष्ट और बाध्यकारी प्रावधान लागू करने की योजना है जिसके अंतर्गत एयरलाइनें, यात्रियों के लिए मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के समान जमीन पर हुए पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए पूरी तरह और सख्ती से उत्तरदायी होंगी; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और ऐसी नीति या संशोधन लागू करने के लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ) वर्तमान में, इस मंत्रालय में विमान दुर्घटना के कारण ज़मीन पर नागरिकों को हुए नुकसान के लिए मुआवजे से संबंधित कोई विशिष्ट नीति नहीं है।

*****